>

Title: Need to provide loan assistance to power generating and distribution companies in Rajasthan from Power Finance Corporation and other Agencies of Government of India.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का पावर फाइनेंस कारपोरेशन (विद्युत वित्त निगम) व अन्य वित्तीय एजेंसियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यों की बिजली से संबंधित जो उत्पादन और वितरण करने वाली बिजली कम्पनियां हैं, उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का काम विद्युत वित्त निगम और अन्य एजेंसियां करती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी गति धीमी रहने के कारण राज्यों की विद्युत कम्पनियां वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हाल ही में बीकानेर में राज्य के विद्युत मंत्री ने ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई कि अभी तक भारत सरकार की वित्तीय एजेंसियों से अपेक्षित ऋण उपलब्ध नहीं हुआ है, जबकि कुछ माह पूर्व भारत सरकार के तत्कालीन विद्युत मंत्री जयपुर में एक समारोह में सम्मिलित हुए और घोषणा की कि हमने राजस्थान की बिजली कम्पनियों को पांच हजार करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। मैं भी उस प्रोग्राम में था। मेरा कहना है कि राजस्थान में उपभोक्ताओं को बिजली के डिमांड नोटिस जमा कराए बहुत समय हो गया है। बिजली कम्पनियों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सामान्य वर्ग के लोगों को भी कुओं के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं और राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को भी कुओं पर कनेक्शन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है और एक ही रटारटाया जवाब आता है कि कम्पनियों की वित्तीय हालत खराब है।

महोदय, एक तरफ हम सिंचाई के साधन विकसित नहीं कर पा रहे हैं और सिंचाई के साधन विकसित नहीं होने के कारण देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हो रही है और दूसरी तरफ कुओं में जो पानी है, उसके लिए बिजली कम्पनियां कनेक्शन नहीं देंगी, तो सिंचाई के साधन कैसे विकसित होंगे? यह एक मूल प्रश्न है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के विद्युत मंत्री से मांग करता हूं कि राजस्थान की बिजली उत्पादन और वितरण कम्पनियों को भारत सरकार के विद्युत वित्त निगम व अन्य वित्तीय एजेंसियों से अति शीघ्र ऋण उपलब्ध करवाएं, जिससे बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। जिनके डिमांड नोटिस जमा हैं, उन्हें बिजली के कनेक्शन मिल सकें, कुओं के कनेक्शन मिल सकें, जिससे कि सिंचाई के साथ विकसित हो सकें।